पेंशन संकट: EPFO सदस्य-पेंशनभोगियों की संघर्ष

श्रम, वस्त्र और कौशल विकास पर संसदीय स्थायी समिति ने EPFO के तहत सदस्य-पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन ₹1,000 को संशोधित करने की तत्काल आवश्यकता पर सही ध्यान दिया है। यह राशि अगस्त 2014 में कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) 1995 के तहत स्थापित की गई थी और एक दशक से अधिक समय से अपरिवर्तित रही है।

व्यंग्यात्मक रूप से, भाजपा नेतृत्व वाली सरकार 2014 में पेंशन वृद्धि के लिए श्रेय लेती रही है, हालांकि उसने केवल कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा पहले से घोषित निर्णय को लागू किया था। 2014 में जब यूपीए ने ₹1,000 की न्यूनतम पेंशन का प्रस्ताव रखा था, तब भाजपा, जो तब विपक्ष में थी, ने इसे अपर्याप्त बताया था, और वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने इसे "कृपादान" कहा था और कम से कम ₹3,000 की मांग की थी।

by OJAANK IAS

पेंशन के लिए वर्तमान वित्तीय आवंटन

₹980 करोड़

वार्षिक आवंटन

न्यूनतम पेंशन भुगतानों पर वर्तमान सरकारी खर्च का औसत

₹9,250 करोड़

ईपीएस कोष

2024-25 के लिए केंद्र का योगदान (वेतन का 1.16%)

₹10,000 करोड़ से अधिक

भविष्य का अनुमान

2025-26 के लिए अपेक्षित योगदान

वर्तमान में, सरकार न्यूनतम पेंशन भुगतानों के लिए वार्षिक औसत ₹980 करोड़ का आवंटन करती है। इस आंकड़े को तीन गुना करने की आवश्यकता होगी ताकि कोई सार्थक वृद्धि हो सके। इसके अलावा, केंद्र ईपीएस कोष में वेतन का 1.16% (₹15,000 मासिक वेतन सीमा तक) का योगदान देता है, जिसे 2024-25 के लिए ₹9,250 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है और 2025-26 में ₹10,000 करोड़ से अधिक होने की उम्मीद है।

सरकार की वित्तीय प्रतिबंध

सरकार की स्थिति

सरकार का तर्क है कि वह पेंशन प्रणाली पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं उठा सकती, क्योंकि मौजूदा आवंटन पहले से ही काफी व्यापक हैं।

अधिकारी कोष योगदान में वृद्धि का उल्लेख करते हैं, जो आगामी वित्त वर्ष में ₹10,000 करोड़ से अधिक होने की उम्मीद है।

हितधारक के सुझाव

अतिरिक्त व्यय को प्रबंधित करने के लिए कई व्यवहार्य सुझाव संबंधित प्राधिकरणों को प्रस्तुत किए गए हैं।

ये प्रस्ताव श्रम और वित्त मंत्रालयों के साथ-साथ EPFO को सीधे भी प्रस्तुत किए गए हैं।

सरकार की अनिच्छा के बावजूद, विशेषज्ञों का सुझाव है कि उचित योजना और संसाधन आवंटन के साथ, सार्वजनिक वित्त को अस्थिर किए बिना पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि की जा सकती है।

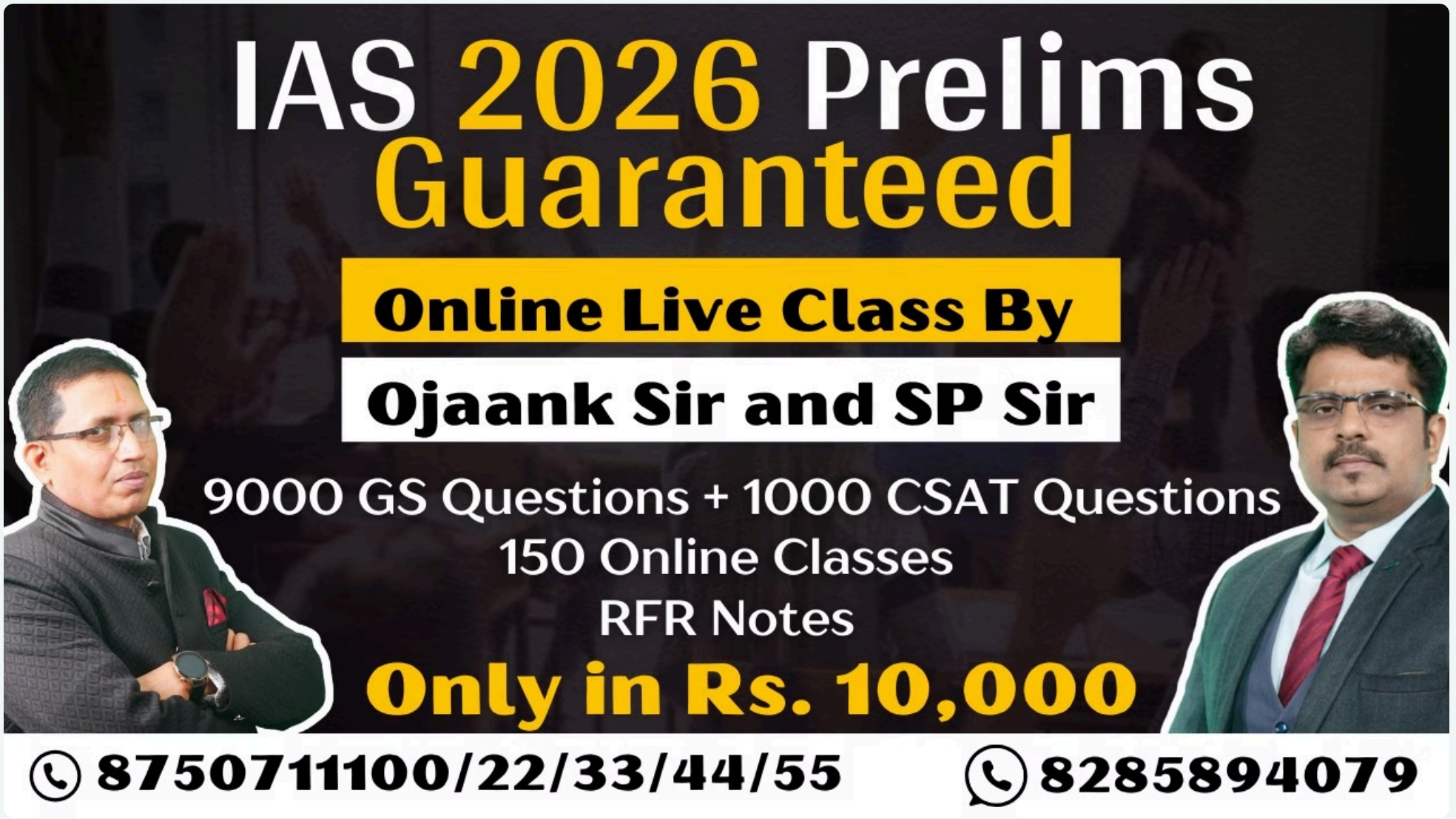

IAS 2026 Prelims की तैयारी अब होगी Guaranteed के साथ! 🔥📚
Ojaank Sir और SP Sir की Online Live Classes में मिलेगा Top Level Guidance✅

💡 **9000 GS Questions**
💡 **1000 CSAT Questions**
💡 **150 Online Live Classes**
💡 **RFR Notes**

💥 **ये सब कुछ सिर्फ ₹10,000 में! सपना नहीं अब रियलिटी बनेगा IAS बनना! 🚀**

Download Ojaank App Now Link :- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ojaank

Course Link - https://ojaankias.akamai.net.in/new-courses/518

📢 **Limited Seats | पहले आओ पहले पाओ**

Ojaank IAS में Admission लेने लिए दिए गए link पर Click करके Form भरें - https://docs.google.com/forms/d/1PzN1wR9JewyqDUCQY4kP60HuoefjYTVnmIL69PIRmxc/edit

अधिक जानकारी के लिए तुरंत Call करें :- 8750711100/22/33/44/55

👉🏻 **Ojaank Sir के साथ सीधा Whatsapp से जुड़ें : 8285894079**

पेंशन दरों का ऐतिहासिक संदर्भ

1

2014 से पहले

कई EPFO सदस्यों के लिए ₹1,000 से कम पेंशन दरें, जिससे वृद्धजनों के लिए वित्तीय कठिनाई हुई

2

2014 यूपीए प्रस्ताव

कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार ने कार्यालय छोड़ने से पहले ₹1,000 की न्यूनतम पेंशन योजना की घोषणा की

3

अगस्त 2014

भाजपा सरकार ने पहले से घोषित ₹1,000 की न्यूनतम पेंशन को लागू किया

4

2014–2024

महंगाई और जीवन-स्तर में वृद्धि के बावजूद न्यूनतम पेंशन राशि में कोई संशोधन नहीं किया गया

₹1,000 की न्यूनतम पेंशन दशक से अधिक समय से स्थिर है, भारत भर में महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तनों और बढ़ते जीवन-लागत के बावजूद। विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने इस राशि को अपर्याप्त बताया था, लेकिन अपने लंबे कार्यकाल में इसमें वृद्धि नहीं की।

उच्च पेंशन आवेदनों के मुद्दे

मांग नोटिस

कई आवेदकों को अब कई लाख रुपये के योगदान की मांग करने वाले नोटिस मिलते हैं, लेकिन उन्हें पेंशन की राशि या बकाया पर कोई स्पष्टता नहीं मिलती है।

संचार की कमी

आवेदकों को आवेदन की स्थिति के बारे में अपडेट ट्रैक करने के लिए केवल ऑनलाइन खाते पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि EPFO द्वारा आधिकारिक संचार जारी नहीं किया जाता है।

अविश्वसनीय गणना

स्पष्टता प्रदान करने के बजाय, आवेदकों को अस्वीकरण के साथ एक पोर्टल-आधारित कैलकुलेटर का उपयोग करना पड़ता है, जिसमें सटीकता की कोई गारंटी नहीं होती है।

उच्च वेतन पर आधारित पेंशन का विकल्प चुनने वाले लोगों के आवेदनों को EPFO द्वारा संभालने से कई सेवानिवृत्त लोगों के लिए महत्वपूर्ण भ्रम और वित्तीय अनिश्चितता पैदा हो गई है, जिन्हें अपने अधिकारों के बारे में स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं मिलता है।

छूट प्राप्त संस्थानों के लिए चुनौतियां

आवेदन अस्वीकृतियां

प्राधिकरणों ने छूट प्राप्त संस्थानों के सदस्यों के उच्च पेंशन के आवेदनों को उचित स्पष्टीकरण या औचित्य के बिना सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया है।

पेंशन रद्दीकरण

पहले मंजूर की गई उच्च पेंशनों को पर्याप्त नोटिस या स्पष्ट तर्क के बिना रोक दिया गया है, जिससे पेंशनभोगियों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है।

पारदर्शिता की कमी

निर्णय लेने की प्रक्रियाएं अस्पष्ट हैं, जिससे प्रभावित पेंशनभोगियों को अपने लाभों को कम या अस्वीकार क्यों किया गया है, इसके बारे में कम जानकारी मिलती है।

स्थिति छूट प्राप्त संस्थानों के सदस्य-पेंशनभोगियों के लिए विशेष रूप से गंभीर है, जो अतिरिक्त नौकरशाही बाधाओं का सामना करते हैं और अक्सर अपने पेंशन आवेदनों को अस्वीकार कर दिए जाने या मौजूदा लाभों को कम कर दिए जाने पर कोई उपाय नहीं पाते हैं।

Get full NCERT RFR Mentorship (3rd Month) Course from Ojaank App Now.

Date - (03-04-2025) आज के प्रमुख 2 प्रश्न Attempt करो तो जाने 👇👇👇

Link - https://ojaankias.akamai.net.in/new-courses/526

Question 1. Which of the following best explains the essence of secularism as introduced in the chapter?

1. **Equal promotion of all religions by the State**
2. **Dominance of the majority religion.**
3. **State funding of religious festivals.**
4. **Ending all forms of religious domination.**
5. **Question**

Question 1. निम्नलिखित में से कौन सा अध्याय में प्रस्तुत धर्मनिरपेक्षता के सार को सर्वोत्तम रूप से समझाता है?

1. **राज्य द्वारा सभी धर्मों को समान प्रोत्साहन**
2. **बहुसंख्यक धर्म का प्रभुत्व**
3. **धार्मिक उत्सवों के लिए राज्य द्वारा वित्तपोषण**
4. **सभी प्रकार के धार्मिक वर्चस्व को समाप्त करना**

Question 2. What is the significance of 'principled distance' in Indian secularism?

1. The state gives equal preference to all religious laws
2. The state may intervene in religion when constitutional values are at stake
3. The state follows religious scriptures while drafting laws
4. All religions must stay away from politics

Question 2. भारतीय धर्मनिरपेक्षता में 'सिद्धांतबद्ध दूरी' का क्या महत्व है?

1. **राज्य सभी धार्मिक कानूनों को समान वरीयता देता है**
2. **जब संवैधानिक मूल्य दांव पर हों तो राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है**
3. **राज्य कानून बनाते समय धार्मिक ग्रंथों का अनुसरण करता है**
4. **सभी धर्मों को राजनीति से दूर रहना चाहिए**

पेंशन नीति में राजनीतिक विरोधाभास

विपक्ष के वादे

भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए ₹1,000 को "नगण्य" बताया था और कम से कम ₹3,000 की मांग की थी

शासन की वास्तविकता

सत्ता में आने के बाद, उनके द्वारा मांगी गई वृद्धि को लागू करने में विफल रहे

नीति में स्थिरता

सत्ता में दशक भर होने और लागत में वृद्धि होने के बावजूद, न्यूनतम पेंशन में कोई संशोधन नहीं किया गया

श्रेय लेना

पूर्व सरकार (यूपीए) द्वारा पहले से घोषित नीति को लागू करने का दावा कर रहे हैं

पेंशन नीति के राजनीतिक प्रबंधन से विपक्ष के वक्तव्य और शासन के कार्यों के बीच महत्वपूर्ण विरोधाभास उजागर होता है। विपक्ष में रहते हुए ₹1,000 न्यूनतम पेंशन की भारी आलोचना करने के बावजूद, भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने अपने विस्तारित कार्यकाल में इसी राशि को बनाए रखा है।

पेंशनभोगियों पर वित्तीय प्रभाव

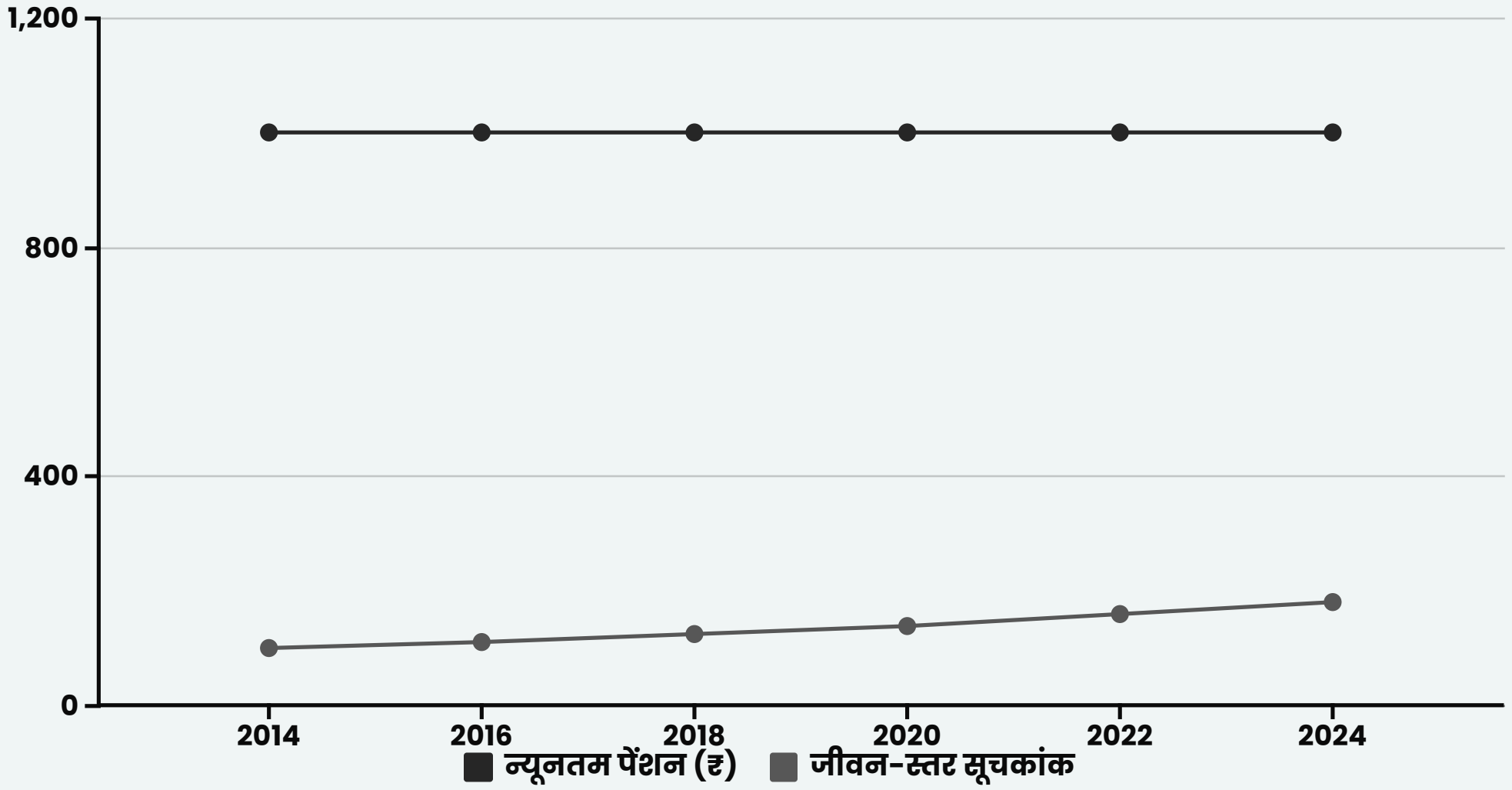

जबकि न्यूनतम पेंशन 2014 से ₹1,000 पर स्थिर रही है, जीवन-स्तर में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। यह चार्ट दिखाता है कि पिछले दशक में पेंशनभोगियों की क्रयशक्ति धीरे-धीरे कम हो गई है, क्योंकि महंगाई ने उनकी स्थिर पेंशन भुगतानों की वास्तविक मूल्य को क्षीण कर दिया है।

पेंशन राशि और जीवन-लागत के बीच बढ़ते अंतर ने कई वृद्ध EPFO पेंशनभोगियों को वित्तीय कठिनाइयों की ओर धकेल दिया है, जिनमें से कुछ अपने कार्यकाल के दौरान पेंशन योजना में योगदान देने के बावजूद मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में संघर्ष कर रहे हैं।

पेंशन प्रशासन में पारदर्शिता मुद्दे

आवेदन प्रस्तुत करना

पेंशनभोगी अपने योगदान के आधार पर उच्च पेंशन के लिए आवेदन करते हैं

अस्पष्ट प्रक्रिया

आवेदन एक ऐसी प्रणाली में प्रवेश करते हैं जिसमें आवेदकों को कम दृश्यता या संचार होता है

अप्रत्याशित मांग

कई लोगों को बिना किसी स्पष्टीकरण के बड़े अतिरिक्त योगदान की मांग की जाती है

अस्पष्ट परिणाम

मांग के भुगतान के बाद भी अंतिम पेंशन राशि और बकाया राशि अनिश्चित रहती है

EPFO द्वारा पेंशन दावों के प्रसंस्करण में पारदर्शिता की कमी ने आवेदकों के बीच महत्वपूर्ण भ्रम और चिंता पैदा कर दी है। आवेदन की स्थिति, गणना विधियों या अपेक्षित परिणामों के बारे में स्पष्ट संचार के अभाव में, कई पेंशनभोगी अपने वित्तीय भविष्य की योजना बनाने में असमर्थ हैं।

पेंशन सुधार के लिए सिफारिशें

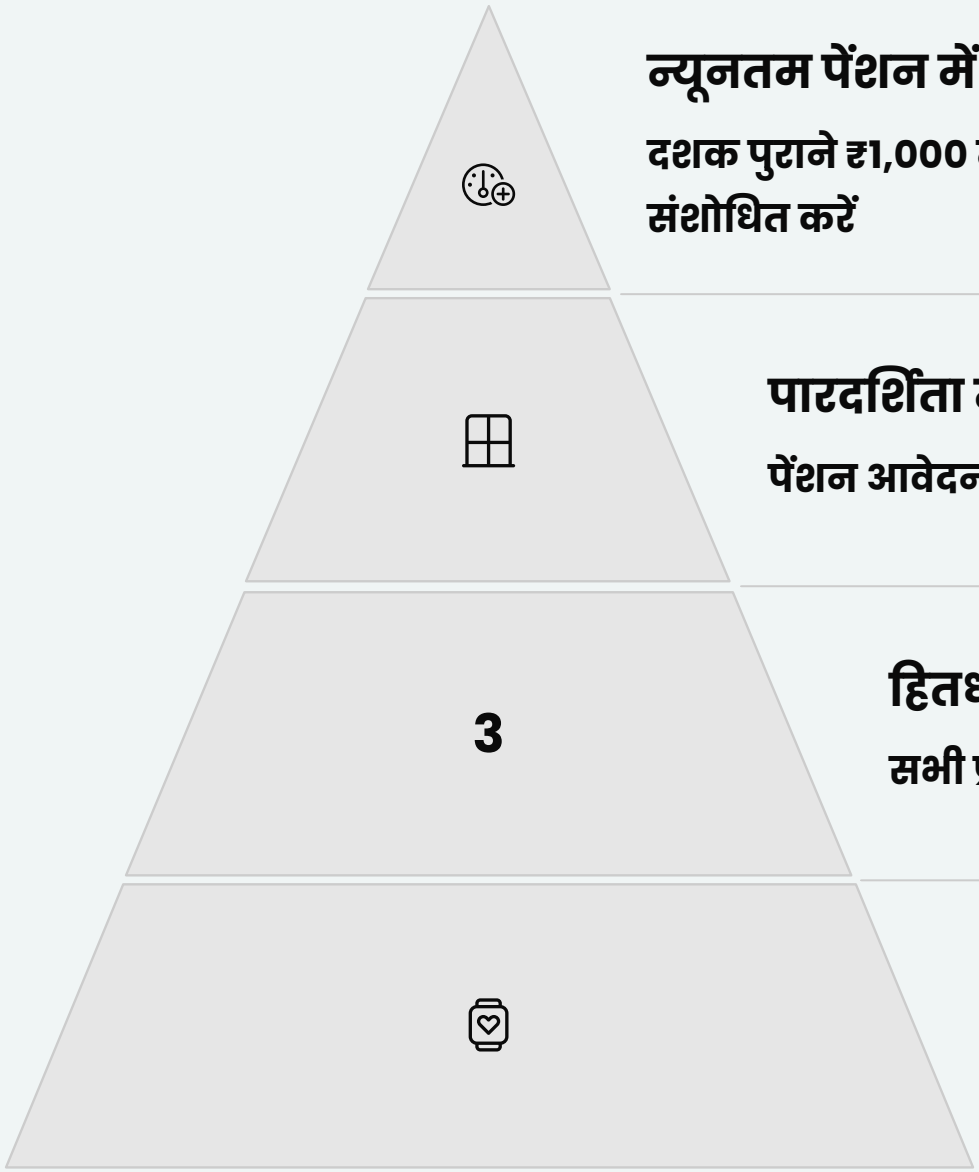

न्यूनतम पेंशन में वृद्धि

दशक पुराने ₹1,000 न्यूनतम को वर्तमान जीवन लागत को दर्शाने के लिए संशोधित करें

पारदर्शिता में सुधार

पेंशन आवेदनों के लिए स्पष्ट संचार प्रोटोकॉल स्थापित करें

हितधारक संलग्नता

सभी प्रभावित पक्षों के साथ व्यापक परामर्श करें

उचित व्यवहार सुनिश्चित करें

छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के पेंशनभोगियों सहित सभी पेंशनभोगियों के लिए प्रक्रियाओं को मानकीकृत करें

केंद्र सरकार को इन दीर्घकालिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए व्यापक हितधारक परामर्श शुरू करना चाहिए। पेंशनभोगियों के सामने आर्थिक वास्तविकताओं को दर्शाते हुए मासिक पेंशन राशि में अर्थपूर्ण वृद्धि करने के कदम उठाए जाने चाहिए। इसके अलावा, सरकार को सभी सदस्य-पेंशनभोगियों के साथ उचित और पारदर्शी व्यवहार सुनिश्चित करना चाहिए, साथ ही स्पष्ट संचार और मानकीकृत प्रक्रियाएं भी होनी चाहिए।

इन सुधारों के बिना, राष्ट्र के कार्यबल में योगदान देने वाले लाखों वृद्ध भारतीय अपने सेवानिवृत्ति वर्षों में वित्तीय कठिनाइयों का सामना करते रहेंगे, जिससे पेंशन प्रणाली के मूल उद्देश्य को कमजोर किया जाएगा।

👉 ऐसी ही UPSC Special Current News PDF के लिए Visit करें हमारी Official Website : www.ojaank.com

👉 DAILY FREE ENGLISH NEWS PDFs Link :
https://www.ojaank.com/books/current-affairs-magazine

👉 DAILY FREE ENGLISH NEWS PDFs Link : https://www.ojaank.com/hindi/books/current-affairs-magazine